

यू.पी.एस.सी

मुख्य परीक्षा अध्ययन सामग्री

सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र – 4

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण,
सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)



Published By

Develop India Group

<http://www.developindiagroup.co.in/>

Published by

Develop India Media Group

Allahabad

Mobile : 08756987953

email : subscriptiondevelopindia@gmail.com

Edition : 2018

Develop India Group Aims

We conduct *Study Material Programme, All India Correspondence Courses, Test Series Programmes* for various competitive exams with our expert faculties. Our aim to provide quality of materials to you in your remote areas.

You can find here

Develop India weekly Newspaper, MINERVA Hindi Monthly Magazine, Books for all competitive Exams, Notes & Study Materials for all competitive exams.

If you want to buy any kind of entrance exam forms/vacancy/previous year question papers, you can contact us.

Copywrite

All matter compile in this notes from various sources believed to be reliable. We published very carefully to this matter, its authors can not take guarantee the occuracy or completeness of any information published herein and neither **Develop India Media Group** nor its authors shall be responsible for any errors, omissions or damage arising out of use of this information.

No part of this notes may be reproduce or transemitted without the written permission of the publisher.

All right reserved.

Note : All disputes with respect to this publication shall be subject to jurisdiction of the courts, tribunals and forums of Allahabad, India.

Contact us

CORPORATE OFFICE

Develop India Media Group

Allahabad

Mobile : 08756987953

emails : subscriptiondevelopindia@gmail.com,

developindiamediagroup@gmail.com

अनुक्रमिका

● भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं	5	● ज्वार	27
● भारत के आर्थिक विकास में बाजार तंत्र की सीमाएं	6	● कृषि अनुसंधान केन्द्र	27
● सभी को रोजगार उपलब्ध कराना	6	● सिंचाई के विभिन्न प्रकार, एवं सिंचाई प्रणाली	28
● समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना	6	● सिंचाई के साधन	28
● गरीबी निवारण	7	● तालाब	28
● आधुनिकीकरण	7	● कुएं एवं नलकूप	29
● 1951 से 1991 (आर्थिक उदारीकरण के पूर्व)	7	● नहरें	29
● 1991 के बाद (नई आर्थिक नीति के पश्चात्)	7	● कृषि गहनता	29
● आर्थिक उदारीकरण के पूर्व नियोजन	7	● कृषि उत्पादकता	30
● नई आर्थिक नीति	8	● टपक सिंचाई	30
● समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण	8	● शुष्क कृषि	30
● ढांचागत सुधार	8	● स्थानांतरित कृषि	31
● विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त परिचय	9	● जैव कृषि	31
● संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय	14	● श्वेत क्रांति	31
● राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम-अब मनरेगा	14	● नीली क्रांति	32
● समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय	14	● कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	32
● वित्तीय समावेशन	17	● विपणन व्यवस्था	33
● सरकारी बजट	17	● भारतीय कृषि की समस्याएं	33
● बजटीय प्रक्रिया	19	● किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी	34
● मुख्य फसलें – देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न	20	● एग्रिस्नेट	34
● भारत में हरित क्रान्ति	20	● प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय	34
● नयी राष्ट्रीय कृषि नीति	24	● न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन	34
● मुख्य फसलें	24	● भारतीय खाद्य निगम की भूमिका	34
● रबी की फसल	24	● सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य	34
● खरीफ की फसल	24	● बफर स्टॉक, खुले बाजार बिक्री एवं विदेशी व्यापार के संबंध में नीतियां बनाना	34
● जायद की फसल	24	● ग्रामीण विकास एवं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अनाज आवंटन	34
● उत्तरी शुष्क अथवा गेहूँ प्रदेश	25	● जन वितरण प्रणाली – उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय	36
● पूर्वी तर अथवा चावल प्रदेश	25	● बफर स्टॉक	36
● पश्चिमी तर अथवा मालावार प्रदेश	25	● खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय	37
● मोटे अनाज वाला प्रदेश	25	● खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और गरीबी	37
● पी. सेन गुप्ता एवं जी.एस. दायुक के कृषि प्रदेश	25	● खाद्य सुरक्षा बिल	38
● हिमालय खण्ड	25	● नए प्रावधान	38
● पूर्वी एवं आर्द्र तटीय खण्ड	25	● पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र	38
● अर्ध-आर्द्र प्रदेश	25	● डेयरी उत्पाद	38
● शुष्क खण्ड	25	● रेशा (फाइबर)	38
● हिमालय खण्ड	25	● उर्वरक	38
● पूर्वी एवं आर्द्र तटीय खण्ड	25	● श्रम	39
● अर्ध-आर्द्र प्रदेश	26	● भूमि प्रबंधन	39
● शुष्क खण्ड	26	● डेयरी कार्यकलाप	39
● कृषि प्रदेशों में विभाजन	26	● भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन	39
● चावल प्रधान क्षेत्र	26	● भारत में भूमि सुधार	43
● चावल की फसल	26	● जमींदारी प्रथा	43
● गेहूँ प्रधान क्षेत्र	27	● भूदान आन्दोलन	44
● गेहूँ की फसल	27		
● ज्वार-बाजरा क्षेत्र	27		

● उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव	44	● क्लोनिंग	84
● औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास	45	● स्टेम सेल तकनीक	84
● निर्गम नीति	47	● मानव जीनोम परियोजना (ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट)	85
● बुनियादी ढांचा – ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि	48	● जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग	86
● कोयला	48	● कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग	86
● पेट्रोलियम	48	● जैवप्रौद्योगिकी का पर्यावरण में योगदान	88
● प्राकृतिक गैस	48	● जैव ईंधन	88
● पवन ऊर्जा	48	● जैव प्रौद्योगिकी पार्क तथा इंक्यूबेटर्स	88
● सौर ऊर्जा	48	● जैव-प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता	89
● लहर ऊर्जा (या तरंग ऊर्जा)	48	● बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संदर्भ में जागरूकता	89
● नदी घाटी परियोजनाएं	48	● संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन	90
● परम्परागत ऊर्जा स्रोत	48	● ओजोन हित सम्बंधी समस्या व प्रयास	90
● गैर-परम्परागत स्रोत	48	● ग्लोबल वार्मिंग/वैश्विक ऊष्णता	91
● निवेश मॉडल	53	● कोपेनहेगन सम्मेलन	92
● निवेश मार्ग तथा प्रक्रियाएं	55	● पर्यावरण संरक्षण सम्बंधी महत्त्वपूर्ण संगठन	92
● विज्ञान और प्रौद्योगिकी – विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव	55	● प्राकृतिक संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ	92
● विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां	59	● विश्व वन्य जीव कोष	92
● अंतरिक्ष विभाग	59	● संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम	93
● सूचना प्रौद्योगिकी	62	● पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग	93
● भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और सहसम्बन्धित तथ्य	62	● जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी रिपोर्ट	93
● आई.टी के लाभ एवं अनुप्रयोग	63	● अम्लीय वर्षा	93
● बायोइन्फॉर्मेटिक्स	63	● यूरो मानक	93
● बायोचिप के लाभ	63	● राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन	93
● अंतरिक्ष	64	● आपदा और आपदा प्रबंधन	94
● प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी (रॉकेट टेक्नोलॉजी)	64	● विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध	95
● भारत में प्रक्षेपणयान के विकास के चरण	64	● आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका	96
● कक्षाएं	65	● निपटने हेतु सुझाव	97
● प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	65	● संचार नेटवर्क एवं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क सइटों की भूमिका	97
● क्रायोजेनिक इंजन	65	● मीडिया की भूमिका	97
● उपग्रह प्रौद्योगिकी	66	● साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें	98
● उपग्रह के प्रकार	66	● साइबर कानून	98
● भारत में उपग्रह संचार प्रणाली (इनसेट)	66	● आईटी अधिनियम 2000	98
● मिशन चंद्रयान	70	● सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008	98
● एन्ड्रिक्स	70	● अधिसूचना एवं नियमावली	98
● कम्प्यूटर	70	● निर्णय (सीएटी)	98
● कम्प्यूटर के अंग	71	● धन शोधन और इसे रोकना	98
● कम्प्यूटर की कार्यप्रणाली एवं विकास	71	● सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन	99
● कम्प्यूटर का विकास	71	● संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध	100
● क्वांटम कम्प्यूटिंग	73	● जाली मुद्रा	100
● सुपर कम्प्यूटर	73	● तस्करी	100
● कम्प्यूटर चायरस	74	● माफिया	100
● कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की पारिभाषिक शब्दावली	74	● विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश	100
● राबोटिक्स	79	1. केंद्रीय सुरक्षा बल (सी.आर.पी.एफ.)	101
● नैनो टेक्नोलॉजी	79	2. त्वरित कार्य बल (आर.ए.एफ.)	101
● नैनो तकनीकी का मूल आधार	80	3. सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)	101
● नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग	80	4. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)	101
● भारत में नैनो तकनीकी	81	5. असम राइफल	101
● बायो टेक्नोलॉजी	82	6. भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)	101
● कोशिका संवर्धन	82	7. रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.)	101
● आनुवांशिक अभियांत्रिकी	82		

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं

औपनिवेशिक काल में आर्थिक विकास के निम्न स्तर के लिए मुख्यरूप से ब्रितानी शासकों की नीतियां जिम्मेदार थीं। उपनिवेशिक शासकों का मुख्य लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं, अपितु अपने देश के आर्थिक हितों को पूरा करना था। परिणामस्वरूप उन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जो कि उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल थे। ब्रिटेन में उत्पादित विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया गया। परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2 प्रतिशत से कम एवं प्रति आय में वृद्धि आधा प्रतिशत से भी कम रह गयी।

स्वतंत्रतापूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र गतिहीनता का शिकार था तथा इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनायी गई भू-राजस्व व्यवस्था थी। भू-राजस्व व्यवस्था का लक्ष्य किसानों की दशा सुधारना नहीं अपितु अधिकतम राजस्व की प्राप्ति था। ब्रिटिश शासकों में सिंचाई, प्रौद्योगिकी विकास एवं उर्वरकों के प्रयोग आदि को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। ब्रिटिश काल में कृषि अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार विकास किया गया, उसके दो लक्ष्य थे—

1. कृषि द्वारा उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व की प्राप्ति।
2. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हेतु नियत भूमिका अदा करना। इस नियत भूमिका का मतलब ब्रिटेन से निर्यात वस्तुओं के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र को बाजार के रूप में विकसित करना एवं ब्रिटेन के लिए आगतों की आपूर्ति करने वाला क्षेत्र बनाना था।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित बदलाव उत्पन्न हुए :

- महाजनों और जमींदारों का एक नया वर्ग जन्मा जो अंग्रेज परस्त था।
- लगान वसूलने वाले विचौलियों का जन्म हुआ।
- अंग्रेजों के अनुकूल काश्तकार, बटाईदार और मजदूर पैदा हुए।
- खेती के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया टप्प हो गयी।
- उत्पादन का स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुरूप बदल गया।
- कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, किन्तु लाभ अंग्रेजी कारखानों को मिला। ब्रिटिश शासकों द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण दो उद्देश्यों से प्रेरित था। प्रथम आयातित माल का भुगतान करना, दूसरा सैनिक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना।

उद्योगों पर प्रभाव

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारतीय औद्योगिक परिदृश्य आत्मनिर्भर प्रकृति का था। शिल्प—कला एवं लघु कुटीर उद्योग अत्यन्त विकसित अवस्था में थे। अंग्रेजों के आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय औद्योगिक

आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। इसके अनेक कारण थे।

राजा महाराजाओं के पद बड़ी मात्रा में समाप्त कर दिए गए जो राज्य अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे उनके पास भी बड़ी मात्रा में संसाधन नहीं थे। फलस्वरूप भारतीय शिल्प एवं लघु कुटीर उद्योगों से निर्मित उत्पादों की मांग करने वाला एक बड़ा बाजार प्रभावित हो गया।

यही वह समय था, जब ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रान्ति की थी। भारतीय उद्योगों के हाथ से निर्मित उत्पादों को ब्रिटेन के मशीनों से निर्मित उत्पादों से प्रतिযোগिता करनी पड़ी। फलस्वरूप भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई एवं भारतीय आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई।

अंग्रेजों के आगमन का भारतीय औद्योगिक परिदृश्य पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारम्भ हुआ इसके पीछे मुख्यरूप से दो परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। प्रथम—अंग्रेजों ने भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास में कुछेक कारणों से रुचि ली। दूसरा— विऔद्योगीकरण के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में श्रमिक बेरोजगार हुए थे जो आधुनिक उद्योगों के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध करा रहे थे। इन दोनों ही परिस्थितियों ने पूंजीगत उद्योगों के लिए आवश्यक दशाएं बना दी थीं। 20वीं शताब्दी तक औद्योगिक विकास चार उद्योगों तक सीमित हो गया था— (1) सूती (2) पटसन (3) चाय बागान (4) कोयला। किन्तु इसे औद्योगिक क्रांति के लिए आधार नहीं माना जा सकता था जिसके अनेक कारण थे जैसे

1. संवृद्धि दर अत्यन्त धीमी थी और जीडीपी में योगदान अत्यन्त कम था।
2. उद्योगों का संकेन्द्रण कुछ स्थानों तक सीमित था जिससे क्षेत्रीय संतुलन बढ़ा।
3. रासायनिक, इंजीनियरिंग, धातु शोधन के उद्योगों का अभाव था। अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी।

विदेशी व्यापार पर प्रभाव

भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटिश हितों के अनुकूल विकसित हुआ। जिसकी विशेषता थी— भारत कच्चे उत्पाद जैसे कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक बन गया और रेशम, ऊनी वस्त्र एवं इंग्लैण्ड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का सामान आयात की मुख्य मर्दें थीं। इंग्लैण्ड का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। श्रीलंका, चीन और ईरान आदि से अत्यल्प व्यापार होता रहा। भारत का निर्यात उसके आयात से अधिक था अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार आधिक्य की स्थिति में बनी रही, किन्तु यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद न था, क्योंकि देश के आन्तरिक भागों में आवश्यक वस्तुओं की कमी

उत्पन्न हुई एवं निर्यात से होने वाले प्रतिफल की प्राप्ति नहीं होती थी।

आर्थिक आयोजन की आवश्यकता

भारत पर 190 वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा इस तरह से शासन किया गया, कि विकास की सभी सीमाएं (अवरु) हो गईं भारत के औपनिवेशिक शोषण और अल्प विकास के कारण बेरोजगारी और गरीबी जैसी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। संकेत साफ है कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो अर्थव्यवस्था न केवल गतिहीन एवं दिशाहीन थी बल्कि उसके सामने बहुत सी समस्याएं विद्यमान थीं जिनका समाधान बहुत ही जरूरी था। बाजार तंत्र पर पूरी निर्भरता से आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। अतः भारत के राजनीतिक नेताओं ने शुरू से ही आर्थिक आयोजन का समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि में भारत में 1951 में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आर्थिक आयोजन की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है :

1. सीमित संसाधनों के द्वारा अनेक अवसरों हेतु निवेश आवश्यकताओं को पूरा करना।
2. देश में विद्यमान क्षेत्रीय, अन्तः-क्षेत्रीय, अन्तः औद्योगिक असमानताओं को दूर करते हुए देश का संतुलित विकास सुनिश्चित करना।
3. देश के संविधान के प्रस्तावना में निहित लोकतंत्रात्मक और समाजवादी राज्य के संकल्पना के वास्तविक अर्थों को प्राप्त करना। लोकतंत्र और समाजवाद आपस में अपने निरपेक्ष स्तर पर विरोधी अवधारणा हैं। लोकतंत्र जहां पर स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्त्व देता है, वहीं समाजवाद समानता के सिद्धान्त पर आधारित होता है। स्वतंत्रता पर बल देने के कारण लोकतंत्रात्मक समाज में निजी क्षेत्र प्रधान हो जाता है और अन्ततः बाजार आधारित व्यवस्था पर निर्भर होता है। निजी क्षेत्र लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य से संचालित होता है। समाजवादी राज्य में समानता पर मुख्य बल देने के कारण राज्य मुख्य उत्पादक इकाई हो जाता है जिसका लक्ष्य अधिकतम कल्याण करना होता है।
4. देश के विकास की भावी जरूरतों का ध्यान में रखते हुए आयात से निर्भरता समाप्त करना और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना।
5. आज के वैश्वीकरण के युग में वैश्वीकरण ने जहां अनेक सम्भावनाएं सृजित की हैं, वहीं अनेक चुनौतियों को जन्म दिया है। हाल का वैश्विक वित्तीय संकट इसका उदाहरण है। इन चुनौतियों को कम करके उपलब्ध अवसरों का प्रयोग देश के विकास की जरूरतों के लिए करना।
6. भारत के आर्थिक विकास में बाजार तंत्र की सीमाएं।
7. विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में संसाधनों का तर्कपूर्ण आबंटन।

आर्थिक आयोजन के उद्देश्य

पिछले छः दशकों में भारतीय आर्थिक आयोजन के अलग-अलग लक्ष्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में घोषित किए गए, किन्तु उन सभी लक्ष्यों में भारतीय आयोजन के सामने प्रमुख रूप से छः लक्ष्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं :

1. तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति।
2. आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास।
3. सभी को रोजगार उपलब्ध कराना।

4. समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना।
5. गरीबी निवारण।
6. आधुनिकीकरण।

1. तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति

भारत में सभी योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य तीव्रतर आर्थिक संवृद्धि की प्राप्ति रहा है। प्रारम्भ से ही हमारे नीति निर्माताओं का यह विश्वास था कि अनेक समस्याओं का समाधान तीव्र आर्थिक संवृद्धि के माध्यम से किया जा सकता है। इसे ही 'ट्रिकल डाउन' रणनीति कहा गया। माना गया कि जैसे-जैसे आर्थिक संवृद्धि होगी अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होगी जिससे देश में विद्यमान गरीबी को दूर किया जा सकता है एवं अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा सकती हैं।

2. आत्मनिर्भरतापूर्ण विकास

- 1951 में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया शुरू होने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, विकास की जरूरतों एवं संसाधन के लिए अन्य देशों पर निर्भर थी। इस पर निर्भरता को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है :
- एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था।
- देश में आधारभूत उद्योगों का भारी अभाव था जिसके कारण उसे बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग वस्तुएं, पूंजीगत पदार्थ, मशीनरी, विद्युत संयंत्र, परिवहन, उपकरण एवं तकनीक का आयात करना पड़ता था।
- देश में विकास के लिए अपने संसाधन नहीं थे क्योंकि बचत अत्यंत कम थी। इस कारण हमें विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता था।
- इस परनिर्भरता के परिणामस्वरूप विकसित देश मनचाही कीमत के साथ-साथ राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल भी करते थे। ब्रितानी काल का हमारा अनुभव भी यह था कि विदेशी व्यापार देश के सम्प्रभुता के लिए संकट बन सकता है।

3. सभी को रोजगार उपलब्ध कराना

गरीबी एवं बेरोजगारी के मध्य मजबूत सह-सम्बन्ध है इस बात को हमारे नीति-निर्माताओं ने समझा था। इसीलिए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम साथ-साथ चलाए गए।

यद्यपि प्रारम्भ से ही रोजगार सृजन को हमने मुख्य लक्ष्य माना था, किन्तु रोजगार के विकास के लिए अलग से कोई भी पृथक योजना नहीं चलाई गई। योजना आयोग का यह विचार था कि निवेश में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि स्वतः हो जायेगी। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसने निवेश के प्रकार में अन्तर नहीं किया। निवेश के द्वारा यदि पूंजी गहन उत्पादन किया जाता है तो अनुपातिक रूप से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। रोजगार के सृजन के लिए श्रम-गहन उत्पादन आवश्यक है। 1977 में जनता सरकार ने इस रणनीति पर पहली बार सर्वाधिक जोर दिया।

4. समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में कमी लाना

इस उद्देश्य को यद्यपि किसी भी पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित नहीं किया गया, किन्तु इसका उल्लेख विभिन्न योजनाओं में